8 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय फिल्मोत्सव के 10 वें संस्करण की शुरुआत होगी। इस बार समारोह की थीम 'साहस' रखी गई है। अभिनेता शाह रुख खान इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यह महोत्सव 17 अगस्त तक चलेगा।

असांजे के प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश सरकार ने लगाई मुहर

- अमेरिकी अर्जी कोर्ट ने स्वीकार की तो आज अमेरिका को मिल सकती है असांजे की सुपुर्दगी

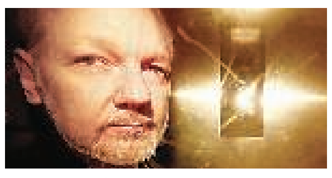

जूलियन असांजे। रायटर

लंदन, प्रेट्र : विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश पर ब्रिटेन के गृह मंत्री ने दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका में असांजे के खिलाफ कंप्यूटर हैकिंग कर गोपनीय दस्तावेज चुराने और उन्हें सार्वजनिक करने का मुकदमा दर्ज है। इसी मामले की जांच के सिलसिले में अमेरिका ने असांजे को प्रत्यर्पित करने की अर्जी ब्रिटिश कोर्ट में दी है। जमानत की शर्तों के उल्लंघन के लिए वह फिलहाल ब्रिटेन में 50 हफ्ते के कारावास की सजा काट रहे हैं। वह बीमार भी हैं।

वैसे असांजे के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है लेकिन ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जावीद ने प्रत्यर्पण आदेश पर बुधवार को ही दस्तखत कर दिए हैं। सरकार की तरफ से यह आदेश शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर कोर्ट प्रत्यर्पण की अमेरिकी अर्जी को मंजूर कर लेता है तो असांजे को बिना समय दिए तत्काल अमेरिका को सौंपा जा सकता है।

साजिद जावीद ने कहा, हमारे पास अमेरिका का प्रत्यर्पण के लिए जायज अनुरोध पत्र आया है। इसलिए प्रत्यर्पण आदेश पर दस्तखत करने में संकोच नहीं हुआ। वैसे स्वीडन में दर्ज दुष्कर्म के मामले में मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण असांजे लंदन जेल में हैं, जहां वह बीमार हैं। बीमारी के चलते वह पिछली सुनवाई में भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे।

शुक्रवार को उनसे जुड़े मामले की सुनवाई जेल में या वीडियो लिंक के जरिये हो सकती है। चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बथनॉट की अदालत में असांजे के मामले की सुनवाई चल रही है। चर्चित भारतीय आरोपियों-विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामलों की भी इसी अदालत में सुनवाई हो रही है।

गूगल व अमेजन जैसी कंपनियों का वर्चस्व खत्म करने की मुहिम तेज

जेएनएन, नई दिल्ली

- अमेरिकी जस्टिस विभाग ने कहा, डिजिटल द्वारपाल बन गई हैं बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां
- अधिग्रहण के जरिये बड़ी कंपनियों के विस्तार पर रोक लगाने की जरूरत बताई

मेकन डेलरहीम। फाइल

तेजी से बदलते डिजिटल वर्ल्ड में गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के एकाधिकार से अमेरिका में भी बेचैनी बढ़ने लगी है। बाजार को बचाने और प्रतिस्पर्धा को जिंदा रखने के लिए इन कंपनियों के वर्चस्व को खत्म करने की मुहिम भी तेज होने लगी है। अमेरिकी जस्टिस विभाग के एंटीट्रस्ट शाखा ने इन बड़ी कंपनियों को 'डिजिटल द्वारपाल' बताते हुए उनके पर कतरने की वकालत की है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए अपने उत्पाद को मुफ्त और सस्ता होने के तर्क के साथ अपने बर्ताव का बचाव करना मुश्किल हो सकता है।

एंटीट्रस्ट शाखा के प्रमुख व असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मेकन डेलरहीम ने कहा कि मौजूदा समय की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ संभावित प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार की जांच में दशकों पहले स्टैंडर्ड ऑयल और एटी एंड टी जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ की गई प्रवर्तन की कार्रवाई के अध्ययन से मदद मिल सकती है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'वर्तमान परिदृश्य से लक्षित होता है कि इंटरनेट सर्च, सोशल नेटवर्क, मोबाइल एवं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक बुक सेल्स समेत अहम डिजिटल क्षेत्र में एक या दो ही उल्लेखनीय खिलाड़ी हैं।'

डेलरहीम ने कहा कि जिस तरह से आज इन बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का बाजार पर एकाधिकार है, कभी स्टैंडर्ड ऑयल की स्थिति भी वैसी ही हुआ करती थी। जिस समय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा था, स्टैंडर्ड ऑयल ने शानदार प्रौद्योगिकी के बल पर बाजार पर एकाधिकार जमा लिया था। हालांकि, उस समय भी उपभोक्ताओं को कम कीमत का लाभ मिलता था।

एंटीट्रस्ट प्रमुख ने कहा कि एटी एंड टी का बर्ताव एकाधिकार से होने वाले नुकसान का ताजा उदाहरण है। कंपनी ने शुरू में स्वतंत्र कंपनियों को अपनी लंबी दूरी की लाइनों से कनेक्ट करने से मना कर दिया था, जिससे इन कंपनियों को नुकसान हुआ। एटी एंड टी ने भी इस तर्क के साथ अपने रवैये का बचाव किया था कि वह ग्राहकों को बेहतर कीमत, सेवा और नवीन तकनीक प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि 1990 में जस्टिस विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी लड़ाई शुरू की थी, जिस पर वेब ब्राउजर प्रदाता नेटस्कैप जैसी दूसरी कंपनियों से मिल रही चुनौतियों को खत्म करने के लिए प्रतिस्पर्धारोधी हथकंडा अपनाने का आरोप लगा था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सपोलर के साथ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किया था, जिसके बाद नेटस्कैप को भारी नुकसान उठाना पड़ा और धीरे-धीरे कंपनी बाजार से ही गायब हो गई।

डेलरहीम ने कहा, 'माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ सरकार के एकाधिकार विरोधी केस की सफलता से गूगल, याहू और एप्पल जैसी कंपनियों के डेस्कटॉप और मोबाइल के वर्चस्व को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।' उन्होंने बड़ी कंपनियों को अधिग्रहण के जरिए अपना विस्तार करने से रोकने की जरूरत भी बताई।

उन्होंने कहा कि नई प्रतिद्वंदी कंपनियों का अधिग्रहण कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह प्रतिस्पर्धारोधी ही होता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने, एकाधिकार को बचाने या प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिग्रहण किया जाता है तो वह ठीक नहीं है। बाजार में केवल कुछ ही कंपनियों का एकाधिकार होने पर नुकसान उपभोक्ताओं को झेलने पड़ते हैं और उन पर कई बार भारी बोझ भी पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि बाजार प्रतिस्पर्धी बना रहे।

प्रौद्योगिकी कंपनियों के वर्चस्व की अमेरिका में संसदीय जांच शुरू

जेएनएन, नई दिल्ली : अमेरिकी संसद कांग्रेस ने मंगलवार को गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के एकाधिकार की जांच शुरू की। सांसदों ने इन कंपनियों की बढ़ती ताकत पर चिंता जताते हुए कहा कि इस उद्योग पर सरकार के ढीले रवैये से फायदा की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है।

सांसदों का कहना था कि इन कंपनियों के चलते समाचार उद्योग से जुड़ी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार में उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। संसदीय दल में शामिल डेमोक्रेट के प्रतिनिधि डेविड सिसिलीने ने कहा कि समाचार उद्योग से जुड़ी कंपनियों के राजस्व का बड़ा हिस्सा गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को चला जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते विज्ञापन से स्थानीय पत्रकारिता के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है।

पक्ष में वोट के लिए नेतन्याहू ने जताया मोदी का आभार

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद नरेंद्र मोदी, धन्यवाद भारत।'

- संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत ने इजरायल के पक्ष में किया था मतदान

दरअसल गत छह जून को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत ने इजरायल के पक्ष में मतदान किया था। नेतन्याहू ने इसी समर्थन के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। इजरायल ने यूएन की इस संस्था में फलस्तीन के गैर सरकारी संगठन शहद को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का विरोध किया था। अपने संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने के लिए फलस्तीन ने यह प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह प्रस्ताव 14 के मुकाबले 28 मतों से गिर गया।

ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने इजरायल समर्थित किसी प्रस्ताव के पक्ष में यूएन में मतदान किया। भारत फलस्तीन के समर्थन के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत की नीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वर्ष 2015 में यूएनएचआरसी में गाजा में हिंसा से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा था। तब इसे प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच की मजबूत होती केमिस्ट्री के तौर पर देखा गया था।

प्रत्यर्पण बिल पर हांगकांग में नहीं थमा बवाल

विरोध ▶ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार दूसरे दिन हुई झड़प

सरकारी दफ्तर बंद, विधायी परिषद की बैठक स्थगित

हांगकांग में प्रत्यर्पण बिल को लेकर गुरुवार को भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रायटर

हांगकांग, रायटर : विवादित प्रत्यर्पण कानून को लेकर हांगकांग में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रस्तावित कानून को रद करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी गुरुवार को भी सड़कों पर डटे रहे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ कई बार झड़प हुई। माना जा रहा है कि प्रत्यर्पण कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर इस पूरे हफ्ते के लिए सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। हांगकांग की विधायी परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गई। विरोध प्रदर्शन के चलते बुधवार को भी परिषद में प्रत्यर्पण कानून संबंधित बिल पर चर्चा नहीं हो पाई थी।

आरोपितों और संदिग्धों को चीन प्रत्यर्पित करने वाले इस प्रस्तावित कानून के विरोध में विधायी परिषद के पास का क्षेत्र जंग का मैदान बन गया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने वहां डेरा डाल रखा है। गुरुवार को जब उनके लिए भोजन के पैकेट और मॉस्क पहुंचाए जा रहे थे तब पुलिस के जवान उसमें रुकावट खड़ी करने लगे। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी उनकी ओर दौड़े। इस पर दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। प्रत्यर्पण कानून को रद करने की मांग को लेकर बीते शनिवार को भी लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया था।

चीन समर्थक हांगकांग की नेता कैरी लैम कह चुकी हैं कि प्रत्यर्पण कानून पर पीछे नहीं हटा जाएगा। विधायी परिषद में बुधवार से इस बिल पर चर्चा होनी थी। इसी के विरोध में बुधवार से ही हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमा हैं।

विधायी परिषद के पास हो रहे विरोध प्रदर्शन में स्कूली छात्र भी शामिल हुए। दिन के समय हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन विधायी परिषद की बैठक स्थगित होने के बाद यह संख्या कुछ कम हो गई। 20 साल के छात्र स्टीफेन चान ने कहा, 'अगर बिल पर चर्चा होगी तो हम फिर लौट आएंगे।'

हांगकांग को सौंपने में ब्रिटेन की थी यह शर्त : ब्रिटेन ने 1997 में इस शर्त के साथ चीन को हांगकांग सौंपा था कि वह इसकी स्वायत्तता बरकरार रखेगा। लेकिन चीन नियंत्रित हांगकांग इस समय सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन के दौर से गुजर रहा है।

हांगकांग पर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव

हांगकांग, एएफपी : प्रत्यर्पण कानून को लेकर हांगकांग पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने विवादित कानून की आलोचना करते हुए कहा कि हांगकांग के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जना चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने भी कहा कि उनकी सरकार प्रस्तावित कानून के प्रभाव को लेकर चिंतित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं प्रदर्शनकारियों की चिंता की वजह को समझ सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि चीन और हांगकांग इसका समाधान निकाल लेंगे।

चीन ने प्रदर्शनों को दंगा बताया

बीजिंग, एएफपी : हांगकांग में हो रहे प्रदर्शनों को चीन ने दंगा करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'जो कुछ हो रहा है वह एक समूह द्वारा प्रायोजित दंगा है।'

चुनाव में प्रतिद्वंद्वी के बारे में विदेश से लेंगे जानकारी : ट्रंप

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के बारे में किसी अन्य देश से जानकारी लेना चाहेंगे। ट्रंप का यह बयान चौंकाने वाला है क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से इन आरोपों को ठुकराते रहे हैं कि उन्होंने 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस की मदद से जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल मामले की जांच भी हो चुकी है। जांचकर्ता रॉबर्ट मुलर को ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम और रूस के बीच साठगांठ के कोई सुबूत नहीं मिले।

डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

इस सवाल पर कि अगर रूस या चीन जैसा कोई देश इस तरह की जानकारी देने की पेशकश करता है तो आप क्या करेंगे? ट्रंप ने बुधवार को एबीसी न्यूज से कहा, 'मुझे लगता है कि आप यह सुनना चाहते हैं। सुनने में कुछ गलत नहीं है।' उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि यह अमेरिका के चुनाव में किसी विदेशी हस्तक्षेप जैसा होगा। ट्रंप ने कहा, 'यह कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर उनके पास जानकारी है तो मेरा मानना है कि मैं इसे लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इसमें कुछ गलत है तो मैं एफबीआइ (संघीय जांच एजेंसी) से इसका पता लगाने को कह सकता हूं।'

ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं

तेहरान, एएफपी : अमेरिका और ईरान के बीच उपजे तनाव को खत्म करने के मकसद से जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो ने गुरुवार को यहां ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की। बैठक के बाद खामनेई ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है और वे इस लायक नहीं हैं कि उनके साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया जाए।

ईरान के सरकारी टीवी चैनलों के अनुसार, मुलाकात में खामनेई ने एबी से स्पष्ट कहा कि ट्रंप के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है और ना ही वह उनके किसी प्रश्न का जवाब देंगे। एबी के तेहरान आने से पहले मंगलवार को ट्रंप ने फोन पर उनसे बात की थी। खामनेई से मुलाकात से पहले एबी यहां राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मिले। एबी ने उनसे कहा कि खाड़ी क्षेत्र में उपजे तनाव को खत्म करने के मकसद से ही वे इस दौरे पर आए हैं। रूहानी ने इस पर कहा कि इस तनाव के मूल में अमेरिका खुद है। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी खत्म कर दें तो स्थितियां खुद सामान्य हो जाएंगी।

ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों पर हमले

दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक ओमान की खाड़ी में गुरुवार को पेट्रोलियम पदार्थों से लदे दो जहाजों पर हमला कर दिया गया। इससे एक जहाज में आग लग गई। एपी

दुबई, रायटर : दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य से कुछ दूरी पर ओमान की खाड़ी में गुरुवार सुबह दो तेल टैंकरों पर हमला किया गया। हमले का शिकार एक टैंकर ताइवान और दूसरा नॉर्वे का है। दोनों मालवाहक जहाजों पर पेट्रोलियम पदार्थ नाफ्था भरा था। ताइवान ने कहा है कि उसके टैंकर को टॉरपीडो से निशाना बनाया गया। इस हमले के पीछे किसका हाथ था, यह अभी पता नहीं चला है। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है।

- एक माह पहले भी इसी क्षेत्र में चार तेल टैंकरों पर हुए थे हमले

समुद्र के जिस क्षेत्र में ये हमले हुए, उस पर अधिकार रखने वाले ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से अभी कोई बयान नहीं आया है। बहरीन के पास डेरा जमाए अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े ने कहा कि हमले की सूचना मिलते ही वे मदद की तैयारी में जुट गए थे। हमले की खबर आते ही खाड़ी देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका को लेकर कच्चे तेल की कीमतों में चार प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला। ठीक एक महीने पहले इसी क्षेत्र में चार तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब ने उस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था।

ईरान ने 44 नाविकों को बचाने का किया दावा : ईरान ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने हमले का शिकार हुए तेल टैंकरों पर मौजूद 44 नाविकों को बचाया है। इन लोगों को सुरक्षित बांदर-ए-जस्क बंदरगाह पर ले जाया गया है। इससे पहले भी चार तेल टैंकरों पर हमले हो चुके हैं।

पोलैंड में एक हजार सैनिक और तैनात करेगा अमेरिका

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पोलैंड में एक हजार अमेरिकी सैनिक और तैनात किए जाएंगे। यूरोपीय देश पोलैंड में फिलहाल 4500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ट्रंप के इस एलान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए रूस के सांसद व्लादिमीर दहाबरोव ने खुली चेतावनी दी है कि अगर रूस पर हमला हुआ तो जवाबी हमले में पोलैंड को बर्बाद कर दिया जाएगा। दहाबरोव ने मॉस्को में कहा, पोलैंड में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ अमेरिका वहां जासूसी ड्रोन भी तैनात करने की योजना बना रहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रजेज डूडा के साथ सामरिक सहयोग से जुड़े साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि पोलैंड, अमेरिका से 32 उन्नत एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग ने पोलैंड में और सैनिकों की तैनाती का स्वागत किया है।

ब्रिटेन में पीएम चुनाव के पहले दौर में सबसे आगे रहे बोरिस जॉनसन

- पहले राउंड के मतदान में मिले 114 मत
- दस में से तीन उम्मीदवार होड़ से बाहर

लंदन, रायटर : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में बोरिस जॉनसन सबसे आगे निकल गए हैं। इसके लिए गुरुवार को हुए पहले राउंड के मतदान में बोरिस को सबसे ज्यादा 114 मत मिले। जबकि इस राउंड के बाद तीन उम्मीदवार बाहर हो गए हैं। अब मैदान में सात उम्मीदवार बच गए हैं।

सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुनने के लिए पार्टी के कुल 313 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। पहले राउंड के कुल दस उम्मीदवारों में से बोरिस जॉनसन को 114, मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट को 43, पर्यावरण मंत्री माइकल गोव को 37 और पूर्व ब्रेक्जिट मंत्री डोमिनिक रॉब को 27 मत मिले। जबकि हाउस ऑफ कॉमंस की पूर्व नेता एंड्रिया लीड्सम, मार्क हार्पर और एस्तर मैकवे बाहर हो गए। पहले दौर का चुनाव जीतने पर बोरिस ने कहा, 'कंजरवेटिव पार्टी में मेरे साथियों आपका धन्यवाद। मैं पहले दौर का चुनाव जीतने पर खुश हूं, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है।' टेरीजा सरकार में विदेश मंत्री रह चुके बोरिस को कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुने जाने और प्रधानमंत्री बनने की होड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। प्रधानमंत्री टेरीजा ने ब्रेक्जिट समझौते पर संसद में कई बार विफलता हाथ लगने के बाद पिछले माह पीएम पद छोड़ने का एलान कर दिया था। उन्होंने गत सात जून को पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था।

ऐसे हुआ चुनाव

कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र से मतदान कराया गया। पहले राउंड के चुनाव में 16 या इससे कम मत पाने वाले उम्मीदवार बाहर हो गए। जबकि इससे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार अगले दौर में पहुंच गए। अगले दौर के मतदान 18, 19 और 20 जून को कराए जाएंगे ताकि अंतिम दौर के चुनाव में सिर्फ दो उम्मीदवार बचें।

लंदन के वेस्टमिंस्टर में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते टेरीजा मे की सरकार में विदेश मंत्री रह चुके बोरिस जॉनसन के पिता स्टेनली जॉनसन। टेरीजा मे का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में बोरिस जॉनसन सबसे आगे हैं। एएफपी

सिर्फ भीड़ से नहीं मरे माउंट एवरेस्ट पर लोग

दावा

नेपाल सरकार ने सामने रखे तर्क और आंकड़े, इस बार पर्वतारोहण सत्र में माउंट एवरेस्ट पर गए 11 लोगों की मौत हुई है, सरकार मृतकों की संख्या 8 बता रही है जबकि एक लापता है

बीते दिनों एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के कारण जाम की स्थिति बन गई थी। फाइल

काठमांडू, प्रेट्र : दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्वतारोहियों की मौत का कारण केवल भीड़ नहीं हो सकती है। वे ज्यादा ऊंचाई पर पैदा होने वाली बीमारियों, पुरानी बीमारियों और अत्यधिक विपरीत प्रभाव वाले मौसम के चलते भी मौत के शिकार हो सकते हैं। यह दावा नेपाल सरकार ने किया है। पर्वतारोहण के हाल में खत्म हुए सत्र में इस बार माउंट एवरेस्ट गए 11 लोगों की मौत हुई है। नेपाल सरकार इस संख्या को आठ बताती है जबकि एक लापता है।

माउंट एवरेस्ट जाने वालों के लिए यह साल सबसे ज्यादा मुश्किल रहा। वर्ष 2015 के बाद चालू वर्ष में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। नेपाल के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार पर्वतारोहण के लिए आए कुल 16 लोग इस साल काल के गाल में समाए और एक अभी तक लापता है। मृतकों में आठ भारतीय पर्वतारोही शामिल हैं। इनमें से चार माउंट एवरेस्ट के रास्ते में मरे जबकि दो-दो माउंट कंचनजंघा और माउंट मकालू के रास्ते में मौत के शिकार हुए। इस साल पर्वतारोहण के लिए जाने वालों में भारतीय सबसे आगे रहे। उन्होंने कुल 78 अनुमति पत्र सरकार से प्राप्त किए।

नेपाल के पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक डांडूराज घिमिरे ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह की गलत खबरें आ रही हैं, उससे हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ी है। माउंट एवरेस्ट जाने वाले रास्ते में भीड़ का बढ़ना मौत का अकेला कारण नहीं हो सकता। जाम की समस्या तब पैदा होती है जब एक ही समय पर बहुत ज्यादा पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करें। लेकिन चालू सत्र में ऐसा नहीं हुआ। घिमिरे ने बताया कि हिमालय में खतरनाक स्थिति आठ हजार मीटर के बाद पैदा होती है। इसीलिए उसे डेथ जोन कहते हैं। वहां ज्यादा देर तक रहने पर तबीयत बिगड़ने और मौत का खतरा पैदा हो जाता है। पर्यटन विभाग ने बताया है कि 2017 में 366 पर्वतारोहियों को अनुमति पत्र जारी किए गए। 2018 में 346 अनुमति पत्र जारी किए गए। जबकि 2019 में 381 अनुमति पत्र जारी हुए। इस लिहाज से चालू वर्ष में खास ज्यादा अनुमति पत्र जारी नहीं हुए जिससे ट्रैफिक जाम वाली स्थिति पैदा हो।

'आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने ठोस कदम नहीं उठाए'

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने यहां सक्रिय आतंकी गुटों के खिलाफ कुछ अहम कदम तो उठाए हैं, लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अमेरिका ने पाक से आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की वरिष्ठ अधिकारी एलिस जी वेल्स ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन जब तक पाकिस्तान में आजादी से काम करेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बड़े मुद्दे को पुलवामा जैसे हमले खतरे में डाल देते हैं। क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों पर तत्काल रोक की जरूरत है। एलिस ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से आतंकी गुटों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए कहता रहेगा। क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि के लिए यह बहुत जरूरी भी है।

पाक के गुरुद्वारों को संवार कर पर्यटन बढ़ाने की योजना

लंदन, प्रेट्र : प्रॉपर्टी के कारोबार में बड़ा दखल रखने वाले एक ब्रिटिश सिख ने पाकिस्तान के गुरुद्वारों के लिए नया ट्रस्ट गठित कर वहां पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। यह पर्यटन करतारपुर कॉरीडोर के जरिये होगा और इसमें भारत के सिख तीर्थस्थलों को भी जोड़े जाने की योजना है।

लंदन के बी एंड एस प्रॉपर्टी के प्रोपराइटर पीटर विर्दी अपने विर्दी फाउंडेशन के जरिये यह कार्य करेंगे और इसमें 500 मिलियन पाउंड (4,400 करोड़ रुपये) लगाने की योजना बना रहे हैं। यह धनराशि वह स्वयं और उनके मित्र-परिचित खर्च करेंगे। इसके लिए जो गुरु नानकदेव के नाम पर ट्रस्ट बनाया जाएगा। पीटर के अनुसार उन्हें अगर इस सेवा का मौका मिल जाए तो वह खुद को बड़ा भाग्यशाली महसूस करेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर वह आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों सरकारों को योजना से जुड़े सरोकारों के बारे में बताएंगे। अनुमति मिलने पर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

लंदन में पाकिस्तान हाय-हाय के लगे नारे

लंदन, एएनआइ : लंदन में वर्ल्ड बलोच ऑर्गनाइजेशन और बलोच रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले जन जागरण अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में बलोच आबादी और अन्य अल्पसंख्यक तबकों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पाक में खुद को लापता किए जाने की खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से हाल के वर्षों में बलूचिस्तान प्रांत से हजारों लोग पहले पुलिस और सेना की हिरासत में लिए गए और बाद में वे लापता हो गए। इन लोगों के बारे में पूछे जाने पर कोई नहीं बताता, उलटे उत्पीड़न शुरू कर दिया जाता है।